

भारत में कृषि

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में संलग्न है और देश के सकल मूल्य संवर्धन (वर्तमान मूल्य पर) 2016-17 में इसकी हिस्सेदारी 17.4% है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं।
- भारत को 15 कृषि जलवायुविक प्रदेशों में विभक्त किया गया है जिसका आधार प्रदेश विशेष भी भौतिक दशाओं के साथ-साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां भी है।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरकता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ 2016 के साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की भी शुरुआत की गई है।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तीन घटकों में से एक है। अन्य दो घटक हैं- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग।
- आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़ों के लिए वर्षों से ग्राँस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट्स (जीडीपी) पर निर्भर रहने के बाद अब पॉलिसी मेकर्स उसके लिए ग्राँस वैल्यू एडेड (जीवीए) का इस्तेमाल करने के बारे में विचार करने लगे हैं। इसके बारे में बताया जा रहा है...

ग्राँस वैल्यू एडेड

- साधारण शब्दों में कहा जाए तो जीवीए से किसी इकोनॉमी में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है।
- इससे पता चलता है कि तय पीरियड में इनपुट कॉस्ट और रॉ मैटीरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपये के सामान और सर्विसेज का उत्पादन हुआ है।
- इससे यह भी पता चलता है कि किस खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है।

मापन

- नेशनल एकाउंटिंग के नजरिए से देखा जाए तो माइक्रो लेवल पर जीडीपी में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिलता है, वह जीवीए होता है।

- अगर आप प्रॉडक्शन साइड से देखेंगे तो आप इसको नैशनल अकाउंट्स को बैलेंस करने वाला आइटम पाएंगे।

जीडीपी

- जीडीपी कन्स्यूमर के नजरिए से आर्थिक उत्पादन के बारे में बताता है।
- इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश, सरकारी निवेश, सरकारी खर्च और नेट फॉरेन ट्रेड (निर्यात और आयात का फर्क) शामिल होता है।

अंतर

- GVA से प्रॉड्यूसर यानी सप्लाय साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है जबकि जीडीपी में डिमांड या कन्स्यूमर साइड की तस्वीर दिखाता है।

❑ जरूरी नहीं कि दोनों ही आंकड़े एक से हों क्योंकि इन दोनों में नेट टैक्स के ट्रीटमेंट का फर्क होता है।
❑ पॉलिसी मेकर्स ने क्यों जीवीए को भी वेटेज देने का फैसला किया है?
❑ जीवीए से मिलने वाली सेक्टर वार ग्रोथ से पॉलिसीमेकर्स को ये फैसला करने में आसानी होगी कि किस सेक्टर को इंसेंटिव वाले राहत पैकेज की जरूरत है।
❑ जीवीए अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने का सबसे सही तरीका है क्योंकि सिर्फ ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने से यह मान लेना सही नहीं होगा कि उत्पादन में तेज बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि ऐसा तो बेहतर कंफ्लायंस या ज्यादा कवरेज की वजह से भी हो सकता है और इससे असल उत्पादन की गलत तस्वीर मिलती है।

उत्पादन

- ❶ 2016 में मानसून की सामान्य वर्षा और सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों से वर्ष 2016-17 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन संभव हो सका।
- ❷ वर्ष 2016-17 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार चावल का उत्पादन नए रिकार्ड को छूते हुए 110.15 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- ❸ यह पिछले रिकार्ड उत्पादन 106.65 मिलियन टन से 3.50 मिलियन टन अधिक है।
- ❹ गेहूं उत्पादन 2015-16 के 92.29 मिलियन टन उत्पादन से 6.10 मिलियन टन अधिक हुआ है
- ❺ मोटे अनाजों का उत्पादन भी नए रिकार्ड स्तर 44.19 मिलियन टन पर पहुंचने का अनुमान है।
- ❻ यह 2010-11 के सर्वाधिक उत्पादन 43.40 मिलियन टन से 0.79 मिलियन टन अधिक है।
- ❼ यह 2015-16 के 38.25 मिलियन टन उत्पादन से 5.67 मिलियन टन अधिक है।

किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति

- ❶ भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी।
- ❷ इस नीति के कई प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जा रहा है।
- ❸ जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है।

मुख्य कार्यक्रम

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- ❶ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का अनुमोदन 50,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि हेतु किया गया है।

पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य हैं

- ❶ जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना,
- ❷ सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार,
- ❸ पानी का अपव्यय कम करने हेतु और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग,
- ❹ सटीक सिंचाई और पानी बचाने वाली अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि, भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण विधियों को लागू करना आदि।

- ❶ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2016 में पीएमकेएसवाई को एक मिशन के रूप में लागू करने का फैसला किया था।

कृषि क्रेडिट

- ❶ विभाग, आर्थिक सहायता के वायदे वाली योजना के तहत ब्याज पर ऋण देता है।
- ❷ इसके तहत किसानों को 7% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का कर्ज एक साल के लिए देता है। यदि इस ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाता है तो ब्याज की दर 4% सालाना कर दी जाती है।

फसल बीमा

- ❶ प्राकृतिक आपदाओं, कीटनाशकों, बीमारियों और मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया है।
- ❷ इसके अंतर्गत रूपांतरित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना और नारियल, खजूर बीमा योजना आती हैं।
- ❸ इनके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम लागू होने के बाद वर्ष 2013-14 की रबी फसल से बंद कर दी गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2015-16 तक कर दी गई है।
- ❹ एक नई योजना- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016** में खरीफ फसल से लागू की गई है। इसके साथ-साथ पुनर्गठित प्रायोगिक एकीकृत पैकेज बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना भी लागू की गई हैं।

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक समन्वित एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर परामर्श देना है।
- इनमें 07 खाद्यान्न (धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और जौ), 05 दलहनी उपजें (चना, तुअर, मूंग, उड़द और मसूर), 07 तिलहन (मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तोरिया सरसों, कुसुम, निगेरसीड और तिल), कोपरा (सूखा नारियल), कपास, कच्ची पटसन और गन्ना शामिल हैं।

एमएसपी के निर्धारक

- अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न घटकों में उत्पादन लागत (सीओपी) एमएसपी के निर्धारण के लिए बेहद महत्वपूर्ण कारक है।
- मूल्य के अतिरिक्त, आयोग मांग और आपूर्ति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों की प्रवृत्ति, अंतरफसल मूल्यों में समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें और उस वस्तु के एमएसपी का उपभोक्ताओं पर प्रभाव और भूमि तथा जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समुचित इस्तेमाल का भी ध्यान रखता है।
- अतः मूल्य नीति लागत जोड़ पर है, हालांकि लागत एमएसपी का महत्वपूर्ण निर्धारक होती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

- भारत में कृषि क्षेत्र में नए रिकार्ड बन रहे हैं। वर्ष 2016-17 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन होने का अनुमान है जो एक रिकार्ड है।
- यह 2013-2014 के पिछले रिकार्ड उत्पादन से 4% अधिक है। इस उपलब्धि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने देश में प्रौद्योगिकी के विकास, प्रदर्शन और हस्तांतरण के जरिए इसमें योगदान किया है।
- खेतों में कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य कार्यक्रमों के जरिए, कई कार्य किए गए हैं।
- प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, सुधार, प्रदर्शन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कई अन्य पहलें की गई हैं।

मिट्टी और जल उत्पादकता

- देश के प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों, उप-प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्रों, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (1992), कृषि

पारिस्थितिकीय क्षेत्रों (2015) और उप-कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एल्यूपी) ने एनबीएसएस भूमि जीओ पोर्टल विकसित किया है।

- इससे मिट्टी, जमीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल वृद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र/क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकूल, लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी मिलती है।
- राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने जीआईएस प्लेटफॉर्म पर एन्ड्रॉएड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है ताकि भूमि उपयोग नियोजन और प्रबंधन के लिए गांव और खेत स्तर पर, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए वेब आधारित सहायता प्रणाली स्थापित करने में मदद मिल सके।

फसल सुधार

- मुख्य रूप से नई किस्मों/अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न जैविक तथा अजैविक महत्व की संकर सहनशील किस्मों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।
- विकसित की गई 209 किस्मों में से 117 अधिक उत्पादन देने वाली अनाज की संकर किस्में थीं।
- अनाज की इन फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूँ की, 24 मक्का की, 5 रागी की, 3 बाजरा की और एक एक ज्वार, जौ, कंगनी, कोदो बाजरा, छोटा बाजरा तथा प्रोसो बाजरा की थी।

फसल प्रबंधन

- मक्का-गेहूँ और चावल गेहूँ प्रणाली में दीर्घावधि खेती के प्रयोगों से संकेत मिले हैं कि चावल और मक्का की खेती, गेहूँ के खेत में करने से बोई फसल प्रभावित नहीं होती।
- गर्मियों में छिड़काव सिंचाई से संबंधित आधुनिक तकनीकों के जरिए जल के उपयोग से हरे चने की उत्पादकता बढ़ने से 205-7 की तुलना में सम्राट किस्म में अधिक स्थिरता का संकेत मिला है।
- छिड़काव सिंचाई से पानी कम (26.3 प्रतिशत) इस्तेमाल हुआ, जल उत्पादकता अधिक (43.2%) रही और बाढ़ सिंचाई के मुकाबले प्रतिफल (28.4%) बेहतर रहा।

पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन

- सभ्यता की शुरुआत से ही, कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन गतिविधियां मानव जीवन का अभिन्न अंग रही हैं।

- इन कार्यों ने न केवल भोजन की जरूरतों को पूरा किया है और पशुधन का विकास किया है। जलवायु और स्थलाकृति अनुकूल होने के कारण पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन ने भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- भारत के पास पशुधन और मुर्गीपालन की विशाल संपदा है जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका रहती है।
- 19वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में करीब 300 मिलियन गाय, 65.07 मिलियन भेड़ें, 135.2 मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन शूकर हैं।

पशुधन उत्पाद

- पशुधन उत्पाद और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हैं, दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों बेहद जरूरी हैं।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार, 2015-16 के दौरान पशुधन क्षेत्र की मौजूदा उत्पाद दर 5,91,691 करोड़ रुपये रही जोकि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पाद की 28.5% है।
- सतत मूल्य के अनुसार पशुधन उत्पाद की कीमत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का लगभग 29% होती है।
- भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर बना हुआ है।

दुग्ध उत्पादन

- 2015-16 और 2016-17 में दूध का उत्पादन क्रमशः 15.55 करोड़ टन और 16.54 करोड़ टन हुआ।
- इस दौरान दूध के उत्पादन में सालाना 6.37% की वृद्धि हुई।
- 2016-17 में प्रतिव्यक्ति दूध की उपलब्धता लगभग 355 ग्राम प्रतिदिन थी।

मांस उत्पादन

- बारहवीं योजना (2012-13) के दौरान मांस उत्पादन 5.95 मिलियन टन था जोकि 2016-17 के दौरान बढ़कर 7.4 मिलियन टन तक जा पहुंचा था।

मत्स्य पालन उत्पाद

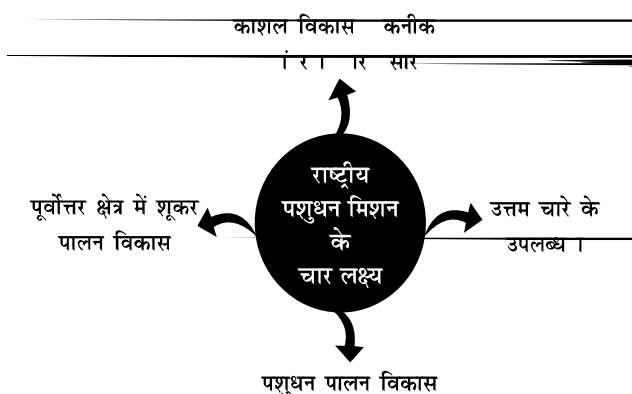
- 2016-17 वित्त वर्ष के दौरान, भारत ने 37,870.90 करोड़ रुपये मूल्य के मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.92% और कृषि जीडीपी (2015-16) का 5.23% था।
- 2017-18 की पहली छमाही में लगभग 5.80 मिलियन टन (तात्कालिक) मछली उत्पादन होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- डेयरी और पॉल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर, पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालिक विकास के लिए, 2014-15 में बारहवीं योजना के अंतर्गत, 2,800 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत की गई थी।
- इस मिशन की स्थापना पशुधन क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य हेतु की गई थी, जिसके अंतर्गत पशुओं के लिए उत्तम चारे की उपलब्धता में सुधार, जोखिम कवरेज, प्रभावी विस्तार, ऋण के प्रवाह में सुधार और पशुपालकों आदि को संगठित करना है।

पशुधन स्वास्थ्य

- संकरण कार्यक्रमों की मदद से मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ, मवेशियों में विभिन्न रोगों का खतरा बढ़ गया है।



- इनमें से कुछ रोग विदेशी पशुओं से भी फैलते हैं।
- रुग्णता और मृत्युदर को कम करने की दिशा में, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें पॉलीक्लीनिकों, पशु अस्पतालों, चिकित्सालयों और प्राथमिक उपचार केंद्रों के अलावा घुमंतु पशु चिकित्सालयों की मदद से बेहतर उपचार उपलब्ध करा रही हैं।
- राज्यों में मौजूदा जांच प्रयोगशालाओं के अलावा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक केंद्रीय और पांच क्षेत्रीय रोग जांच प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है जो पूरी तरह काम कर रही है।
- रोगनिरोधी टीकाकरण की मदद से मवेशियों और पॉल्ट्री के रोगों को रोकने के लिए आवश्यक टीके देशभर में 27 पशु चिकित्सालय टीका उत्पादन इकाइयों में बनाए जा रहे हैं।

□□□

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन सा/से कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति के घटकों में सम्मिलित है/हैं—
1. उच्च गुणवत्ता के बीज व रोगमुक्त पौधेरोंपण सामग्री की आपूर्ति
 2. कृषि बाजार ढाँचे का विकास
 3. संस्थानिक ऋण तक पर्याप्त एवं आसान पहुँच
 4. महिलाओं के लिए शिशु गृह
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1, 2 व 3
(d) 1, 2, 3 व 4
2. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. आयोग अंतर्राष्ट्रीय कीमत अंतर-फसल कीमत तुल्यता, कृषि एवं गैर कृषि के बीच व्यापार की शर्तों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।
 2. आयोग वर्तमान में 25 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
3. निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है/हैं—
- | पुरस्कार | प्रदान करने वाली संस्था |
|----------------------|---------------------------|
| 1. बोरलॉग पुरस्कार — | कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि. |
| 2. गोपाल रत्न — | भारत सरकार |
| 3. बोयरमा पुरस्कार — | विश्व खाद्य संगठन |
- कूट—
- (a) 1 व 2
(b) 2 व 3
(c) 1 व 3
(d) 1, 2 व 3
4. गोकुल मिशन है—
- (a) भारत में पाए जाने वाले सभी दुधारू पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्धता के द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
 - (b) देशी नस्ल के गोवंशीय पशुओं का विकास व सुधार
 - (c) A और B दोनों
 - (d) न तो A न ही B
5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—
1. भारत मत्स्य उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
 2. भारत पशुधन के क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

Answer Key:-

1. (d)

2. (a)

3.(d)

4.(b)

5.(d)